आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 13.04.2025
समय 0720

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे घोषित करेगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा– सरकार राज्य के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
- शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत चौथान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
- और... कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षा– 2025 तथा सुधार परीक्षा (द्वितीय) 2024 का परीक्षाफल आगामी 19 अप्रैल को पूर्वाह्न ग्यारह बजे घोषित करेगा।

परिषद कार्यालय में शनिवार को आहूत परीक्षाफल समिति की बैठक में समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल परिषद की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर देख सकते हैं।

इस वर्ष 2 हजार 268 व्यक्तिगत और 1 लाख 11 हजार 420 संस्थागत परीक्षार्थियों सहित कुल 1 लाख 13 हजार 688 परीक्षार्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए। वहीं कुल 1 लाख 9 हजार 699 विद्यार्थियों ने बारहवीं की बोर्ड परीक्षा दी।

उपनल कर्मचारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ठोस और प्रभावी नीति बनाकर उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का काम जल्द शुरू करेगी। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नियमितीकरण प्रक्रिया से उपनल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। उपनल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि सरकार राज्य के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार नीतिगत बदलावों के द्वारा उपनल कर्मियों के आर्थिक और समाक्जिक स्तर को बेहतर करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल का उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन कल से देहरादून में शुरू हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश भाग ले रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने बताया कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले उत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों ने वर्ष 2024 में 100 प्रतिशत से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया है।

सम्मेलन में न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया।

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने अपने संबोधन में कहा कि मध्यस्थता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमें बुनियादी ढांचे पर और अधिक काम करना होगा और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होगी तथा अन्य देशों की तरह ऑनलाइन विवाद समाधान को बढ़ावा देना होगा।

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेन्द्र जी ने उत्तराखंड के सभी तीर्थस्थलों और पवित्र नदियों सहित सभी पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी और कहा कि डिजिटलीकरण व पेपरलेस कोर्ट आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।

लोकार्पण/शिलान्यास

स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा के विकासखंड थलीसैंण अंतर्गत चौथान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा अधिक से अधिक लाभ उठाने का अनुरोध किया।

श्रीनगर विधानसभा भ्रमण के दौरान उन्होंने थलीसैंण चौथान क्षेत्र के ग्राम पंचतोड़ा, पाटो, डडोली तल्ली व सेरामाण्डे गांव के बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा उन्होंने धारकोट पहुंचकर जनसंपर्क किया और ग्रामीणों से संवाद करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने गणतखाल–डडोली तल्ली–सेरामाण्डे सड़क से सेरामाण्डे गाँव तक नवनिर्मित मोटर मार्ग का लोकार्पण भी किया।

इसके साथ ही डॉ. रावत ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, डडोली तल्ली में निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया और छात्र–छात्राओं व शिक्षकों से संवाद कर शैक्षणिक गतिविधियों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि विकास के प्रकाश को प्रत्येक गाँव तक पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है जिससे ग्रामीण जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल व संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं सहज रूप से प्राप्त हों। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार जनता के हित में निरंतर कार्य कर रही हैं, जिससे जनता को प्रत्यक्ष तौर पर त्वरित लाभ भी मिल रहा है।

सहस्त्रधारा

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। श्री जोशी ने देहरादून में आयोजित बैठक में इस बात पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने सहस्त्रधारा क्षेत्र में पार्किंग और प्रवेश शुल्क के संबंध में जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने सहस्त्रधारा में पर्यटकों की बढ़ती आमद के बीच व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी व सुचारू बनाने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

बैसाखी पर्व

आज बैसाखी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बैशाखी का त्योहार मुख्य रूप से रबी फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वैसाखी, विशु, बोहाग और बिहू, की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कामना की कि ये पर्व लोगों को राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फसल के मौसम के दौरान मनाए जाने वाले ये त्योहार देश की समृद्ध सामाजिक परंपराओं और विविधता में एकता का प्रतीक हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि इन त्योहारों के माध्यम से राष्ट्र किसानों की मेहनत का सम्मान करता है और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि बैसाखी का पर्व उमंग, उत्साह और खुशहाली का प्रतीक है। बैसाखी देश की समृद्धशाली कृषि परंपरा, ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक मूल्यों का उत्सव है, जो किसानों की कठिन मेहनत और योगदान का सम्मान भी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई फसल के कटने से जुड़ा यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा किसान व कृषि संस्कृति का भी परिचायक है।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर....

विधेयकों पर तीन महीने में फैसला लें– राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी। इस खबर पर दैनिक जागरण लिखता है– राष्ट्रपति भी तीन महीने के भीतर राज्यों से आए विधेयकों पर करें फैसला। नवोदय टाइम्स न्यायलय के हवाले से लिखता है – राष्ट्रपति को विधेयकों पर 3 महीने में निर्णय लेना चाहिए।

नेशनल हेराल्ड केस में 661 करोड़ की संपत्तियों को कब्जे में लेगी ईडी इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है।

वहीं अमर उजाला लिखता है नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरु, ईडी का नोटिस ..दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की संपत्तियां हैं मनी लॉन्ड्रिंग में अटैच

राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर पर शीर्षक दिया नेशनल हेराल्ड की संपत्ति कब्जे में लेने के लिए ईडी ने चस्पा किए नोटिस

वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिली है..इस खबर को सभी अखबार ने प्रमुखता से स्थान दिया है।

राष्ट्रीय सहारा लिखता है वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में तीन लोगों की मौत, 138 गिरफ्तार